(b) The names of leading countries exporting electronic components to India are USA, Germany, Japan, South Korea, Taiwan, Hongkong etc.

(c) The total value of export of electronic components was Rs. 190 crores during 1993.

(d) Such information is not maintained separately. However, using the value addition norms applicable to components industry, the import content is estimated to be 70% (cif value of input materials vs. FOB value of export of finished components).

Manufacture of icecream by MNCs

4940. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to open the manufacture of icecream, after shoes, to multinationals and other larger units;

(b) if so, other items reserved for Small Scale Industrial units being given to larger units; and

(c) the reaction of the Small Scale Industry to this developmtnt

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) No, Sir. According to the present policy, no medium/large scale undertaking including multinationals is permitted to manufacture reserved items except under 75% export obligation (in case of export oriented readymade garments units, it is 50% with investment limit of Rs. 3 crores).

No multinational company and/or big industrial house has been allowed to manufacture icecream after it was reserved for small scale. As marketing of icecream is not reserved for small scale, some foreign partnered joint ventures and some big industrial houses have taken up marke ing of icecream.

There has been no recent policy change in this behalf. Earlier also big companies could taken up marketing of icecream.

(c) Does not arise.

Money spent by workmen of Instrumentation Ltd.

4941. SHRI E. BALANANDAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred question 3143 given in the Rajya Sabha on the 23rd December, 1993 and state :

(b) what action has been taken by favour of workers of Bokaro site of Instrumentation Ltd., coming to Delhi to talk on their demands;

(b) whether there is any precedent of such expenditure; and if so, details thereof; and

(c) the steps taken to recover such illegally spent money ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) The T.A. Rules of the company govern expenditure on officials tours.

(b) Yes, Sir, some of the dates being 2-3/3/83, 26-27/4/83 and 6/5/83.

(c) Does not arise.

Resident Engineers with Instrumentation Ltd., Durgapur and Barauni

4942. SHRI MD. SALIM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there are resident engineers posted at Durgapur and Barauni site of the Instrumentation Ltd.; if so, the names of such Engineers and their qualificatiors, in details;

(b) whether it is a fact that these engineers have amassed wealth and are having property disproportionate to their earnings, as reflected in their palatial buildings in Calcutta and at Hajipur; if so, the facts in details; and

(c) whether there has been any probe into the corrupt practices of senior officers of Instrumentation Limited at Bokaro, Durgapur and Barauni; if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) At present, Shri Aroon Chaudhury is posted as resident

engineer at Durgapur site of Instrumentation Ltd. He holds a Diploma in Electrical Engineering.

(b) As per the company's records, the above engineer does not possess wealth disproportionate to his earnings.

(c) No, Sir. The working of the site office is audited by internal audit, statutory auditors, and also the Govt. auditors. There is no report of any corrupt practices.

मध्य प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना

4943. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश में बड़े/भारी उद्योग लगाने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) वर्ष 1991 से 1993 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने हेतु आशय-पत्रों की मंजूरी के लिए 212 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनकी तुलना में, 1-4-94 तक 66 आशय-पत्र जारी किए गए, 56 आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिए गए तथा 86 आवेदन-पत्र या तो वापस ले लिए गए या औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में परिवर्तन के लिये अध्ययन

4944. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संगठनात्मक और प्रबन्ध सम्बन्धी परिवर्तन करने के लिये कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इन परिवर्तनों को लागू करने के लिये कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पिछले तीन वर्षों में संगठनात्मक और प्रबंध परिवर्तनों के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि विभिन्न समितियां जैसे कि श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों संबंधी विशेषज्ञ समिति, श्री एल. के. झा की अध्यक्षता में आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग और डा. अर्जुन सेन गुप्त की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों से संबंधित नीति की समीक्षा के लिए गठित समिति ने क्रमशः वर्ष 1980-82, 1983-84 और 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उनकी सिफारिशों में स्वायत्तता, धारक कंपनियों का गठन, समझौता ज्ञापन आदि जैसे कई प्रकार के विषय शामिल थे। इस सम्बन्ध में सरकार ने कार्रवाई की थी और सिफारिशों को लागू किया था।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया निवेश

4945. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में अब तक किये गये कुल निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उपक्रमों का वार्षिक उत्पादन कितना है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम को हुए लाभ अथवा घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इनमें से किसी उपक्रम को निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) दिनांक 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 6 उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें किए गए पूंजीनिवेश, वार्षिक उत्पादन और अर्जित लाभ अथवा उठाई गई हानि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।